तीन शीर्ष भारतीय जिन्हें जेल में होना चाहिये

क्या ऐसे तीन शीर्ष भारतीय छांटे जा सकते हैं जिन्हें बिना जमानत, अनिश्चित काल के लिये जेल में डालने से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार घट सकता है, प्रशासन की साख बढ़ सकती है, और लोकतंत्र में देश की जनता का विश्वास मज़बूत हो सकता है। हां, आज के दिन ऐसे तीन व्यक्ति गिने जा सकते हैं। ये हैं- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय, किंगफ़िशर एयर लाइन्स के मालिक विजय माल्या। मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी सुब्रत रॉय की खेल व खिलाड़ियों पर धनवर्षा की ख्याति और विजय माल्या की हर तरह के सत्ता-गलियारों में विश्वसनीयता के बावजूद।

मनमोहन सिंह सुभ्रतो राय विजय माल्या

मनमोहन क्यों? नौ वर्ष के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनका हर मंत्रालय आर्थिक घोटालों का अड्डा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ होने के नाते वे ऐसे नासमझ तो नहीं हो सकते कि घोटाले साक्षात होते रहें और उन्हें मन कभी न लगे। यही नहीं प्रधानमंत्री के रूप में घोटालों की फ़ाइलें, हर चरण पर, उनके पास आती रही हैं। ऐसे मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी दो तरह से बनती है, एक तो घोटाले के षड्यन्त्र में हिस्सेदार होने से और दूसरी घोटाला होने देने में सहयोग देने से। जब कदम-कदम पर बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सम्बन्धित फ़ाइलें देखी हैं तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि यदि प्रारम्भ से नहीं तो किसी न किसी स्टेज पर वे षड्यन्त्र का हिस्सा बने। घोटलों की स्वीकृति देकर, उनके बाहर आने पर लीपा-पोती करके और दोषियें को पूरा प्रश्रय देकर उन्होंने घोटाले सम्पन्न होने में पूरा सहयोग भी दिया है यह सब यदि वे हिस्सा पाने के लिये नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहने के लिये तो कर ही रहे थे। अत: हर घोटाले में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारायें 120 बी एवं 109 तो लगाई ही जानी चाहिये। उनके जेल में रहने से सम्बन्धित घोटालों की जांच कार्यवाही उचित रूप से हो सकेगी। साथ ही अगले प्रधानमंत्री को सबक होगा कि वह कठपुतली बन कर देश की जनता को लूटता देखने से बाज आये।

दरअसल मनमोहन सिंह सार्वजनिक नैतिकता के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। कहते हैं वे पूरी तरह ईमानदार हैं यानी रिश्वत नहीं खाते, पर सभी जानते हैं कि उनकी सत्यनिष्ठा ज़ीरो है। इस मामले में पाखंड और धूर्तता का जैसा मिश्रण उन्होंने पेश किया है वह कोई और राजनीतिज्ञ शायद ही कर सके।

सुब्रत राय क्यों? क्योंकि तमाम छोटे-बड़े प्रतिभूति घोटालेबाज़ों के लिये वह प्रेरणा-स्रोत एवं रोत मॉडल है। उसने हज़ारों करोड़ के काले धन को सफ़ेद करने की 'जादूगरी' में ऐसी महारत दिखाई है कि उच्चतम न्यायालय भी उसके आगे पानी भरने को 'विवश' हो रहा है। उसके मुताबिक यह सारा काला धन उसे लाखों छोटे निवेशकों के द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में दिया गया है। पर ये लाखों निवेशक कौन हैं, उनका अता-पता क्या है, इस पर सुब्रत रॉय ने तो काले धन को सफ़ेद करने का वही तरीका अपनाया है जो सभी राजनीतिक पार्टियां चंदे की फ़र्जी पर्चियां काट कर करती हैं।

आज चिट-फंडों एवं शेयरों के एक के बाद एक घोटाले रोजाना खुल रहे हैं, जिन में हज़ारों-लाखों निवेशकों का पैसा डूब रहा है। ऐसे में सुब्रत रॉय को जेल में डाले रखने से इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों की आंखें खुलेंगी और उनसे कुछ न कुछ कानून का भय समयेगा। विजय माल्या क्यों? मालिकों का कर्मचारियों से काम एवं वेतन का सम्बन्ध होता है। यदि कर्मचारी काम न करें तो मालिक उन्हें काम से हटा देता है। पर यदि कर्मचारी काम करते रहें और मालिक उन्हें वेतन देने से मना करता रहे तो? यह स्थिति है विजय माल्या की किंगफ़िशर एयरलाइन्स की। कर्मचारियों का इतना बकाया वेतन लम्बित हो चुका है कि वे कम्पनी को छोड़ कर जा भी नहीं सकते। माल्या इस फ़िराक में है कि थक-हार कर कर्मचारी भाग जायेंगे और वह कम्पनी को दिवालिया घोषित कर अपना पल्ला झाड़ लेगा। माल्या का असली कारोबार शराब का है। उसी की कमाई से उसने एयरलाइन्स खड़ी की थी। शराब कारोबार के मुनाफ़े से वह आसानी से इन कर्मचारियों का बकाया वेतन दे सकता है। पर हर तरह के श्रम-कानून को घता बता कर, अपने रसूख के चलते, वह उन्हें कोरे आश्वासनों का झांसा देता रहा है। यदि उसे जेल में डाल दिया जाये तो कर्मचारियों को वेतन मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इससे श्रम-कानूनों के प्रति देश के करोड़ों श्रमिकों का विश्वास बढ़ेगा, औद्योगिक मोर्चे पर ऐसे विवादों में कमी आयेगी और माल्या जैसे हज़ारों मुनाफ़ाखोर मालिकों को सही नसीहत मिलेगी। मनमोहन सिंह, सुब्रत रांय और विजय माल्या को जेल में डालने से निश्चित रूप से भारतीय जनतंत्र मजबूत होगा।

तुर्की-ब-तुर्की

सुषमा स्वराज नेता विपक्ष लोकसभा

''बच्चों से बलात्कार और (बलात्कार के) क्रूर एवं वहशी कृत्यों में मौत की सज़ा ही काम आयेगी।''

हमारा कहना है

- ऐसे मामलों के शिकार बच्चों व अन्य पीड़ितों को दोषी की मौत से क्या लाभ मिलेगा? उन्हें मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक रूप से मजबूत करने की कवायद होनी चाहिये ताकि वे दुनिया को स्वस्थ रूप से ले सकें?

  नेता विपक्ष हो कर भी और आपकी आकांक्षा तो प्रधानमंत्री बनने की भी है, आपका अपराध को केवल सज़ा के मानदंड से ही देखना क्या उचित है? क्या समाज में लैंगिक उत्पीड़न, जो घर-घर में होता है, पर रोक लगाने के लिये किसी कार्यक्रम को लेने का आप या आपकी पार्टी में साहस है?

  आपकी पार्टी ने युवाओं द्वारा सेक्स की सहमति को एक न्यूनतम उम्र से जोड़ कर उन्हें अपराधी घोषित कराने का रास्ता खोला है। नाबालिग बच्चों द्वारा की जाने वाली भूलों के लिये उनके मां-बाप और समाज जिम्मेदार होते हैं, जो उन्हें स्वस्थ रूप से यौन-शिक्षा की दीक्षा नहीं देते। क्या इस बारे में आपकी पार्टी को कोई रचनात्मक पहल नहीं करनी चाहिये?

जयराम रमेश केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री

''हमारे देश में चुनाव, सौन्दर्य प्रतियोगिता नहीं होते।'' (राहुल गांधी बनाम नरेन्द्र मोदी 2014 चुनाव के संदर्भ में)

हमारा कहना है

- यह भी तो बताइये कि चुनाव होते हैं- पैसे और गुंडई की प्रतियोगिता!
- चुनाव, पाखंड और झूठे वायदों से भरी कवायद भी होते है, यह भी बताइये।
- अन्ततः चुनाव क्या होते हैं-समाज के प्रभावशाली वर्गों में आपसी बन्दरबांट की जद्दोजहद ही तो। अन्यथा आम जनता के वोटों से चुने, जाने के बाद हर शासक, चाहे वह राहुल गांधी हो या वह नरेन्द्र मोदी हो या कोई भी हो, समर्थों के हितों में सारी नीतियां और सारे संसाधन नहीं गिरवी रख देता?

महंगाई के लिये ग़रीब जिम्मेदार

-मनोज कुमार झा

रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने 7 अप्रैल को बेंगलुरू में एक बेहूदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग़रीब लोग अब फल और अंडे खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इससे पहले बतौर गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने 10 जुलाई, 2012 को यह बयान दिया था कि लोग एक किलो चावल पर एक रुपया ज़्यादा नहीं देना चाहते, पर आइसक्रीम पर आसानी से 20 रुपये खर्च कर देते हैं। अपने बयानों से अभी तहलका मचाने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री वेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़े, उतना ही अच्छा है। पिछले साल दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि एक परिवार की मासिक जरूरतें पूरी करने के लिये 600 रुपये काफ़ी हैं। शीला दीक्षित किसी को भेज कर दिल्ली की बेशुमार झुग्गी बस्तियों में कहीं कोई अंधी कोठरी तलाश करवायें, 600 रुपये महीना किराए पर नहीं मिलेगी। बहरहाल, ये सारे नेता हैं, जो जी में आए बक सकते हैं, क्योंकि इनकी जीभ पकड़ कर खींचने वाला कोई नहीं। लेकिन डी सुब्बाराव तो नेता नहीं। दिग्गज अर्थशास्त्री हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। उनकी अक्ल घास चरने कैसे चली गई! या वे भी नेताओं के इशारे पर बयानबाजी करने लगे? जले पर नमक छिड़कना इसे ही कहते हैं। वैसे, इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है। अगले साल आम चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबोने में इन बयानों का अच्छा-खासा रोल होगा। डी. सुब्बाराव जब इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो यह मानना कठिन है कि महंगाई बढ़ने के कारणों का उन्हें ज्ञान नहीं होगा। इतना ज्ञान तो इकोनॉमिक्स के एक साधारण विद्यार्थी को भी होता है। पर सुब्बाराव उस सरकार की चाकरी कर रहे हैं, जिसके मुखिया मनमोहन उनसे भी बड़े अर्थशास्त्री होने का दम भरते हैं। उनकी जो मालकिन हैं सोनिया, उन्हें बेशक आटे-दाल का भाव पता नहीं। वो मारी आंतिनियोत की तरह कह सकती है कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। अपने मायके इटली से चाहें तो पीजा इंपोर्ट करा यूपीए सरकार के खाते में जाते- जाते एक पीजा घोटाला भी दर्ज करा सकती हैं। बहरहाल, कुछ आंकड़ों पर गौर फ़र्माएं। प्रोफ़ेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमिटी का वो आंकड़ा कि देश की 77 फीसदी आबादी 20 रुपये रोजाना की आमदनी पर गुजर कर रही है, बजते-बजते अब फटा ढोल हो चुका। सरकारी आंकड़े दर पेश हैं। योजना आयोग के अनुसार शहरों में 32 रुपये रोजाना और गांवों में 26 रुपये खर्च करने वाले ग़रीबी रेखा से ऊपर हैं। दूसरी तरफ, एक सरकारी एजेंसी एनएसएसओ की 66 वीं राउंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में 35.10 रुपये और शहरों में 66.10 रुपये रोजाना खर्च करने वाले ग़रीबी रेखा से ऊपर माने जायेंगे। अब बाजार भाव- आटा कम से कम 30 रुपये प्रति किलो और बीड़ी का बंडल 12 रुपये का। ईंधन, चीनी, नमक, तेल, दवाइयां, झुग्गी का किराया अलावा। तो ग़रीब लोग आखिर ज़िंदा कैसे हैं? सरकार का कोई मंत्री बयान दे सकता है कि हवा पीकर ज़िंदा रह सकते हैं ग़रीब। पानी पर तो टैक्स है, हवापर नहीं। शुक्र है ख़ुदा का।

पिछले वर्ष योजना आयोग ने दावा किया था कि 2004-2005 और 2009-2010 के बीच ग़रीबों की तादाद घटी है। ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 40.7 करोड़ से घटकर 35.5 करोड़ हो गई। इधर, एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार देश की 60 फीसदी आबादी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाने में अक्षम है। सरकारी आंकड़ों में ही इतना विरोधाभास है। सुब्बाराव कहतें हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी 20 फीसदी बढ़ी है। वहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में 15 हज़ार किसानों ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली। वैसे, यह आंकड़ा विश्वसनीय नहीं लगता। प्रतिवर्ष एक लाख से कम किसान आत्महत्या नहीं करते। महाराष्ट्र सूखे के चपेट में है। शोलापुर में एक किसान डेम से पानी छोड़ने की मांग को लेकर दो महीने से अनशन पर है। घोटाला किंग शरद पवार के भतीजे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस पर कहा कि पानी नहीं है तो क्या करें,डेम में पेशाब बहा दें। इस पर जब थू-थू शुरू हुई तो जनाब ने फ़ौरन माफ़ी मांग ली।

तो देश भर के सारे नेता चुनावी सीजन में चड्डी उतारकर नाचने को तैयार हैं। और जनता महज तमाशबीन है। बहरहाल, अजित पवार ने जो पेशाब बहाने की बात कही तो याद आया, अदम गोंडवी साहब ने पहले ही लिखा था-

'अदम इस सभ्यता के पास देने को नहीं कुछ अब
जो ये संतप्त मानव के लिए पेशाब लाती है।'